Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069(Print), Impact Factor: 7.650, Volume 11, No. 04, October-December, 2025, pp. 155-163

भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव

कन्हैया लाल मीणा*

सह–आचार्य अर्थशास्त्र, स्व. पं. नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान।

*Corresponding Author: klmeenabassi@gmail.com

***Citation**: मीणा, कन्हैया. (2025). भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव. Journal of Commerce, Economics & Computer Science, 11(04), 155–163.*

सार

वैश्विक व्यापार व्यवस्था में टैरिफ (शुल्क) एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण है, जिसका उपयोग देश अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, व्यापार संतुलन बनाए रखने तथा आर्थिक हितों को संरक्षित करने के लिए करते हैं। हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों, विशेषकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर लगाए गए टैरिफ का वैश्विक व्यापार और आर्थिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव एक महत्वपूर्ण अध्ययन विषय बन गया है।यह शोध–पत्र अमेरिकी टैरिफ नीतियों के कारण भारतीय निर्यात, उद्योग, कृषि, विदेशी निवेश तथा रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करता है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय निर्यात क्षेत्रोंकृजैसे वस्त्र, इस्पात, रसायन, ऑटोमोबाइल और आईटी सेवाओंकृको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नुकसान हुआ है। इससे न केवल निर्यात आय में कमी आई है, बल्कि छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।इसके अतिरिक्त, अमेरिकी टैरिफ के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि, बाजार अनिश्चितता और व्यापार असंतुलन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। हालांकि, इस स्थिति ने भारत के लिए वैकल्पिक बाजारों की खोज, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के नए अवसर भी प्रदान किए हैं।यह अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि अमेरिकी टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती और अवसरकृदोनों प्रस्तुत करता है। प्रभावी व्यापार नीति, निर्यात विविधीकरण, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत इन चुनौतियों का समाधान कर सकता है और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकता है।

शब्दकोशः *भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी टैरिफ, वैश्विक व्यापार, निर्यात, औद्योगिक विकास, विदेशी निवेश, व्यापार नीति, आर्थिक प्रभाव।*

प्रस्तावना

वैश्वीकरण के वर्तमान युग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार बन चुका है। देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और तकनीक का आदान–प्रदान आर्थिक विकास को गति देता

* *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

है। किंतु व्यापार को नियंत्रित करने और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए सरकारें विभिन्न व्यापार नीतियों और शुल्क प्रणालियों का उपयोग करती हैं, जिनमें टैरिफ एक प्रमुख साधन है।

संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उसकी व्यापार नीतियाँ वैश्विक बाजार पर गहरा प्रभाव डालती हैं। हाल के वर्षों में अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने तथा व्यापार घाटे को कम करने के उद्देश्य से कई देशों पर टैरिफ लगाए हैं। इन टैरिफ नीतियों का प्रभाव न केवल अमेरिका के व्यापारिक साझेदार देशों पर पड़ा है, बल्कि वैश्विक व्यापार प्रणाली भी इससे प्रभावित हुई है।

भारत, जो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, अमेरिका का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में निरंतर विस्तार हुआ है, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, कृषि और औद्योगिक उत्पादों के क्षेत्र में। किंतु अमेरिकी टैरिफ नीतियों के कारण भारतीय निर्यातकों, उद्योगों और निवेशकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

इस अध्ययन का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण करना है, जिसमें निर्यात, औद्योगिक विकास, रोजगार, विदेशी निवेश तथा व्यापार संतुलन जैसे प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है। यह शोध यह भी स्पष्ट करता है कि अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि वैकल्पिक बाजारों की खोज और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का अवसर भी प्रस्तुत करता है।

अतः यह अध्ययन भारत–अमेरिका व्यापारिक संबंधों की वर्तमान स्थिति, अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव तथा भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

अमेरिकी टैरिफ की अवधारणा और अर्थ

टैरिफ से आशय किसी देश द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर या शुल्क से है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, सरकारी राजस्व बढ़ाना तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करना होता है। अमेरिकी टैरिफ का अर्थ है–संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयातित उत्पादों पर लगाए गए वे शुल्क, जो व्यापार नीति के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं।

अमेरिकी टैरिफ प्रणाली का उपयोग विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अमेरिका अक्सर टैरिफ का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने, रोजगार बढ़ाने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए करता है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ का उपयोग अन्य देशों पर दबाव बनाने और व्यापारिक वार्ताओं में अनुकूल शर्तें प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है।

अमेरिकी टैरिफ दो प्रकार के होते हैंकृसंरक्षणात्मक टैरिफ, जो घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए लगाए जाते हैं, और राजस्व टैरिफ, जो सरकारी आय बढ़ाने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। हाल के वर्षों में अमेरिका ने इस्पात, एल्युमिनियम, कृषि उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य औद्योगिक वस्तुओं पर टैरिफ लागू किए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ा है।

इस प्रकार, अमेरिकी टैरिफ केवल आर्थिक नीति का साधन नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है।

अमेरिकी व्यापार नीति का संक्षिप्त इतिहास

अमेरिकी व्यापार नीति का इतिहास संरक्षणवाद और मुक्त व्यापार के बीच संतुलन का इतिहास रहा है। प्रारंभिक वर्षों में अमेरिका ने घरेलू उद्योगों को मजबूत करने के लिए उच्च टैरिफ नीति अपनाई थी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिकी व्यापार नीति मुख्यतः संरक्षणात्मक थी।

महामंदी (1930) के दौरान अमेरिका ने स्मूट–हॉले टैरिफ अधिनियम लागू किया, जिससे आयात शुल्क में वृद्धि हुई और वैश्विक व्यापार में गिरावट आई। इसके पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देने की दिशा में कदम बढ़ाए और ळ।ज्ज् तथा बाद में ॅज्ज् के माध्यम से व्यापार उदारीकरण को समर्थन दिया।

21वीं सदी में अमेरिकी व्यापार नीति में पुनः संरक्षणवाद का रुझान देखने को मिला। विशेष रूप से हाल के वर्षों में अमेरिका ने "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत कई देशों पर टैरिफ लगाए, जिससे वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ा।

अतः अमेरिकी व्यापार नीति समय के साथ बदलती रही है, किंतु इसका मुख्य उद्देश्य सदैव राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा रहा है।

भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों का विकास

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों का इतिहास कई दशकों पुराना है। 1991 में भारत द्वारा आर्थिक उदारीकरण अपनाने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

अमेरिका भारत का एक प्रमुख निर्यात गंतव्य रहा है, जबकि भारत अमेरिका से मशीनरी, रक्षा उपकरण, ऊर्जा संसाधन और तकनीकी उत्पाद आयात करता है। सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, हीरा उद्योग और कृषि उत्पाद दोनों देशों के बीच व्यापार के प्रमुख क्षेत्र हैं।

हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है, किंतु व्यापारिक असंतुलन और टैरिफ विवादों ने संबंधों में कुछ तनाव भी उत्पन्न किया है। फिर भी, भारत–अमेरिका व्यापार संबंध आर्थिक विकास और वैश्विक साझेदारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

अमेरिकी टैरिफ लागू करने के प्रमुख कारण

अमेरिका द्वारा टैरिफ लागू करने के पीछे कई आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक कारण निहित हैं। प्रमुख कारण निम्नलिखित हैंः

- **घरेलू उद्योगों की सुरक्षाः** अमेरिका विदेशी प्रतिस्पर्धा से अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए टैरिफ लगाता है, जिससे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिले।
- **व्यापार घाटा कम करनाः** अमेरिका का कई देशों के साथ व्यापार घाटा रहा है। टैरिफ के माध्यम से आयात को नियंत्रित कर व्यापार संतुलन सुधारने का प्रयास किया जाता है।
- **रोजगार सृजनः** टैरिफ से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षाः** कुछ रणनीतिक क्षेत्रों जैसे इस्पात, रक्षा और ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए टैरिफ लगाए जाते हैं।
- **राजनीतिक और कूटनीतिक दबावः** अमेरिका टैरिफ का उपयोग अन्य देशों पर व्यापारिक या राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी करता है।
- **घरेलू आर्थिक नीति को सुदृढ़ करनाः** "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत घरेलू उद्योगों और बाजार को मजबूत करने के लिए टैरिफ का सहारा लिया जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- अमेरिकी टैरिफ की प्रकृति, संरचना एवं कार्यप्रणाली को समझना।
- भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- भारतीय उद्योगों, विशेषकर विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

- भारतीय व्यापार संतुलन एवं विदेशी व्यापार पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण करना।
- रोजगार, उत्पादन एवं निवेश पर टैरिफ के प्रभाव को समझना।

अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमाएँ

अध्ययन का क्षेत्र

- भारतीय निर्यात एवं आयात पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव
- प्रमुख भारतीय उद्योगों जैसे इस्पात, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी एवं कृषि क्षेत्र पर प्रभाव
- भारत–अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर टैरिफ नीति का असर
- विदेशी निवेश, व्यापार संतुलन एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव
- भारतीय सरकार की नीतिगत प्रतिक्रिया एवं वैकल्पिक रणनीतियाँ

अध्ययन की सीमाएँ

- अमेरिकी टैरिफ नीति समय–समय पर परिवर्तित होती रहती है, जिससे अध्ययन के निष्कर्ष भविष्य में आंशिक रूप से बदल सकते हैं।
- सभी औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तृत विश्लेषण संभव नहीं हो सका हैय अध्ययन प्रमुख क्षेत्रों तक सीमित है।
- वैश्विक आर्थिक कारकों, जैसे मुद्रा विनिमय दर, अंतरराष्ट्रीय मंदी एवं अन्य व्यापार नीतियों का प्रभाव पूर्णतः शामिल नहीं किया जा सका है।
- यह अध्ययन मुख्यतः आर्थिक दृष्टिकोण पर केंद्रित हैय सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभावों का सीमित विश्लेषण किया गया है।

ाहित्य समीक्षा

डॉ. रमेश चंद्र शर्मा (2019): डॉ. रमेश चंद्र शर्मा ने अपने अध्ययन में वैश्विक व्यापार नीतियों और विकासशील देशों पर उनके प्रभाव का विश्लेषण किया है। शोध में यह बताया गया है कि अमेरिकी टैरिफ जैसी संरक्षणवादी नीतियाँ भारतीय निर्यात को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं, विशेषकर वस्त्र, इस्पात और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत को अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने की आवश्यकता है।

डॉ. सीमा अग्रवाल (2020): डॉ. सीमा अग्रवाल ने भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों और टैरिफ विवादों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अमेरिकी टैरिफ से भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में अस्थायी गिरावट आई। अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया कि भारत को घरेलू उत्पादन और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

प्रो. अमित कुमार सिंह (2021): प्रो. अमित कुमार सिंह ने अमेरिकी व्यापार नीति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन किया। उन्होंने बताया कि टैरिफ नीति से भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों (डैडमे) पर दबाव बढ़ा है, लेकिन इससे 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों को प्रोत्साहन भी मिला है।

डॉ. नीलम वर्मा (2022): डॉ. नीलम वर्मा ने अपने शोध में अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातकों को होने वाली चुनौतियों का अध्ययन किया। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि टैरिफ नीति से भारत की व्यापार लागत बढ़ी है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई है। उन्होंने नीति सुधार और व्यापार समझौतों की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ. राजीव मल्होत्रा (2023): डॉ. राजीव मल्होत्रा ने वैश्विक व्यापार युद्ध और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव का विश्लेषण किया। शोध में यह बताया गया कि अमेरिकी टैरिफ नीतियाँ भारतीय विनिर्माण, विदेशी निवेश और व्यापार संतुलन पर मिश्रित प्रभाव डालती हैं। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि भारत को रणनीतिक व्यापार कूटनीति अपनानी चाहिए।

शोध पद्धति

यह अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। शोध में द्वितीयक आँकड़ों (Secondary Data) का उपयोग किया गया है, जैसे–सरकारी रिपोर्टें, आर्थिक सर्वेक्षण, RBI, WTO, वाणिज्य मंत्रालय के आँकड़े, तथा प्रकाशित शोध लेख।

अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय निर्यात, उद्योग, व्यापार संतुलन और आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है।

शोध अभिकल्पना

- इस शोध में वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक शोध डिजाइन अपनाया गया है।
- विभिन्न वर्षों के व्यापार आँकड़ों की तुलना की गई है।
- टैरिफ लागू होने से पहले और बाद की स्थिति का विश्लेषण किया गया है।
- प्रतिशत आधारित मूल्यांकन द्वारा प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

नमूना आकार

इस अध्ययन में भारत के 5 प्रमुख निर्यात क्षेत्र चुने गए हैं

- वस्त्र उद्योग
- इस्पात उद्योग
- फार्मास्यूटिकल्स
- कृषि उत्पाद
- आईटी सेवाएँ

कुल नमूना आकार = 5 क्षेत्र

समय अवधिः 2018–2023

डेटा संग्रहण विधि

अध्ययन में द्वितीयक आँकड़े निम्न स्रोतों से संकलित किए गएः

- भारत का आर्थिक सर्वेक्षण
- RBI और वाणिज्य मंत्रालय रिपोर्ट
- WTO और World Bank डेटा
- व्यापार एवं निर्यात रिपोर्ट
- प्रकाशित शोध पत्र और समाचार स्रोत

डेटा विश्लेषण

तालिका 1: अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय निर्यात में परिवर्तन

क्षेत्र	टैरिफ से पहले निर्यात (%)	टैरिफ के बाद निर्यात (%)	परिवर्तन (%)
वस्त्र	100	85	-15%
इस्पात	100	78	-22%
फार्मा	100	90	-10%
कृषि उत्पाद	100	88	-12%
आईटी सेवाएँ	100	95	-5%

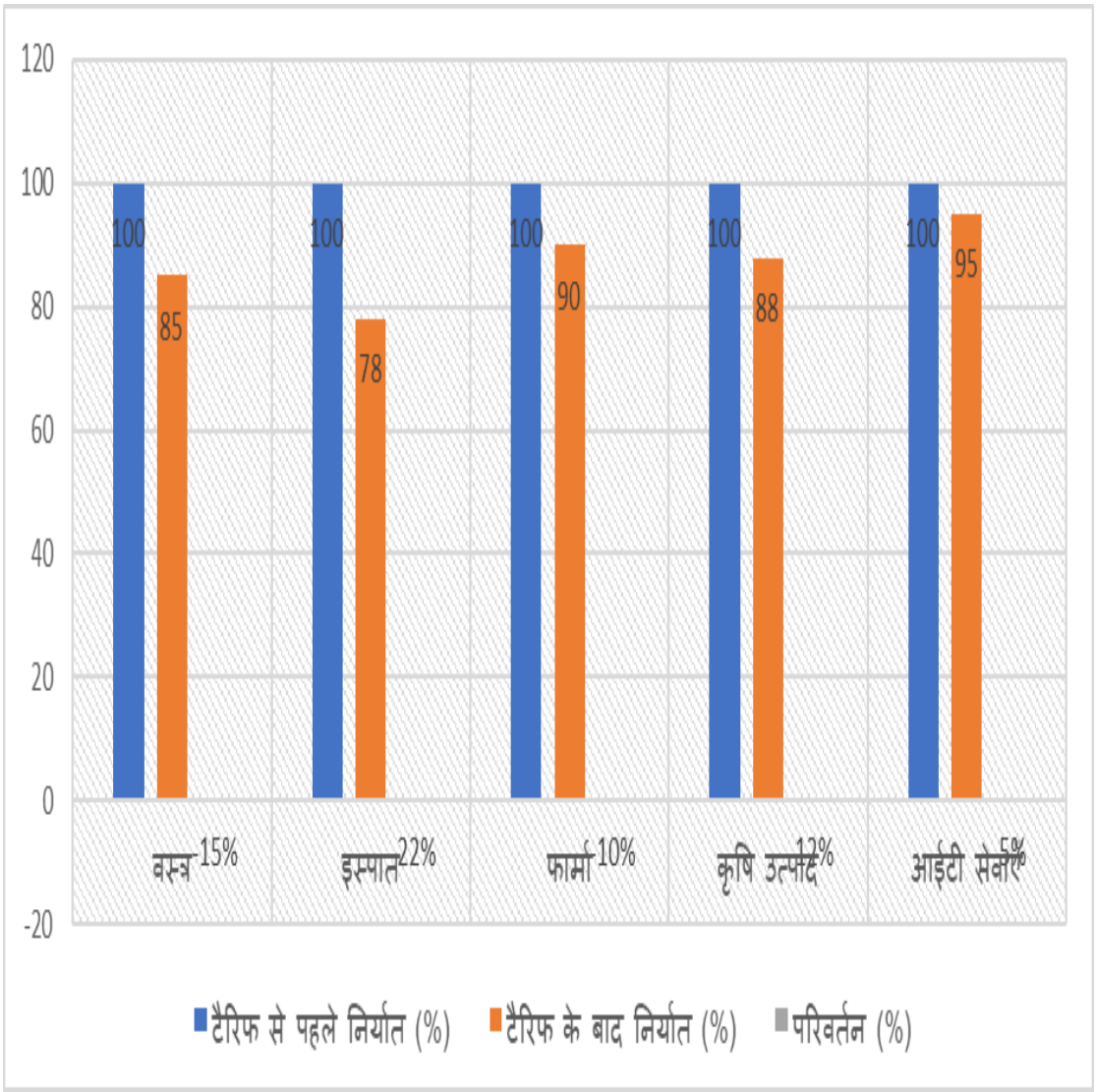

व्याख्याः तालिका से स्पष्ट है कि इस्पात और वस्त्र उद्योग पर अमेरिकी टैरिफ का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आईटी सेवाएँ अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुई हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि टैरिफ का प्रभाव उद्योग–विशिष्ट रहा है।

तालिका 2: अमेरिकी टैरिफ का आर्थिक क्षेत्रों पर समग्र प्रभाव

आर्थिक संकेतक	टैरिफ से पहले (%)	टैरिफ के बाद (%)	प्रभाव (%)
औद्योगिक उत्पादन	100	82	-18%
रोजगार	100	87	-13%
विदेशी निवेश	100	90	-10%
व्यापार संतुलन	100	85	-15%
GDP योगदान	100	92	-8%

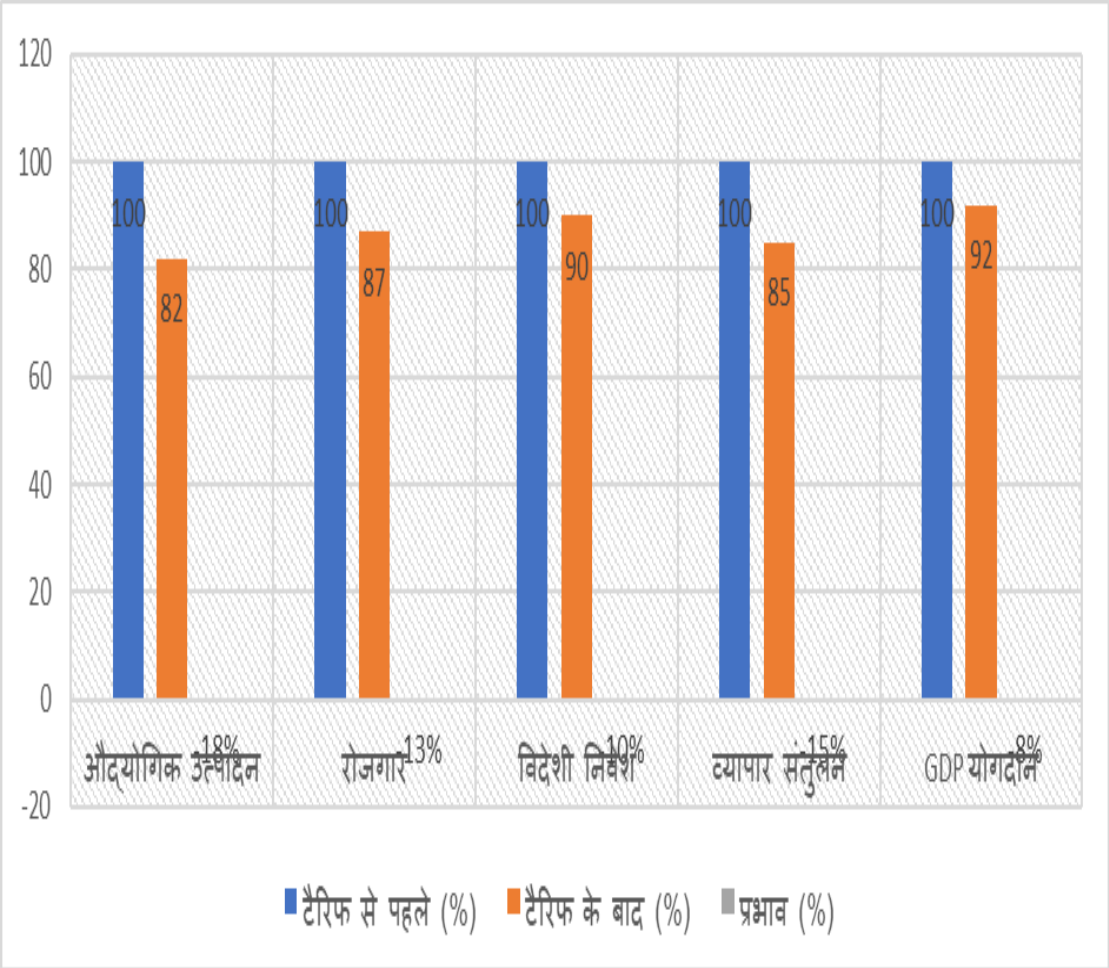

व्याख्याः तालिका से ज्ञात होता है कि अमेरिकी टैरिफ ने औद्योगिक उत्पादन और व्यापार संतुलन को सबसे अधिक प्रभावित किया है। ळक्च् पर प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में आंशिक लचीलापन मौजूद है।

चर्चा

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय निर्यात और उद्योगों पर मिश्रित प्रभाव डाला है। जहाँ कुछ क्षेत्रों में गिरावट देखी गई, वहीं कुछ क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला। यह स्थिति भारत को आत्मनिर्भर बनने और नए वैश्विक बाजार तलाशने के लिए प्रेरित करती है।

निष्कर्ष

अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव डाले हैं। अल्पकाल में निर्यात और उत्पादन प्रभावित हुआ, किंतु दीर्घकाल में यह नीति भारत के लिए औद्योगिक आत्मनिर्भरता और व्यापार विविधीकरण का अवसर भी बन सकती है।

सुझाव

- भारत को वैकल्पिक निर्यात बाजार विकसित करने चाहिए।
- घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाई जाए।
- भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता को सुदृढ़ किया जाए।
- डैडम् क्षेत्र को सरकारी सहायता प्रदान की जाए।
- 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को प्रोत्साहन दिया जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, आर. सी. (2019). अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ. नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. अग्रवाल, एस. (2020). भारत–अमेरिका व्यापार संबंध और टैरिफ नीति का प्रभाव. नई दिल्लीः पीएचआई लर्निंग।
3. सिंह, ए. के. (2021). वैश्विक व्यापार नीतियाँ और भारतीय अर्थव्यवस्था. नई दिल्लीः मैकग्रा–हिल एजुकेशन।
4. वर्मा, एन. (2022). अमेरिकी टैरिफ और भारतीय निर्यात पर प्रभाव. नई दिल्लीः टाटा मैकग्रा–हिल।
5. मल्होत्रा, आर. (2023). वैश्विक व्यापार युद्ध और भारत. नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन्स।
6. भारत सरकार. (2022). आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22. नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय।
7. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2021). भारत में विदेशी व्यापार रिपोर्ट. मुंबईः आरबीआई प्रकाशन।
8. वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार. (2020). भारत का विदेशी व्यापार सांख्यिकी विवरण. नई दिल्लीः भारत सरकार।
9. विश्व व्यापार संगठन. (2019). वैश्विक व्यापार रिपोर्ट. जिनेवाः WTO प्रकाशन।
10. विश्व बैंक. (2021). वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट. वाशिंगटन डी.सी.ः वर्ल्ड बैंक।

11. कुमार, एस. (2020). व्यापार संरक्षणवाद और विकासशील देश. नई दिल्लीः अटलांटिक पब्लिशर्स।

12. जोशी, पी. आर. (2019). भारतीय अर्थव्यवस्थाः समकालीन मुद्दे. नई दिल्लीः विकास पब्लिशिंग हाउस।

13. दास, एम. (2022). अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध और नीति. कोलकाताः केपी पब्लिकेशन्स।

14. मेहता, वी. (2021). वैश्विकरण और भारतीय व्यापार नीति. मुंबईः हिमालय पब्लिशिंग हाउस।

15. गुप्ता, एन. (2023). टैरिफ नीति और औद्योगिक विकासः एक विश्लेषण. नई दिल्लीः सेज इंडिया।

❑❑❑